†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बहस के दौरान में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनमें से कई के बारे में मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा यही रहेगा कि मैं उन सब के ब्यौरे में अपने आपको न उलझाऊं, और इस पूरी बहस के दौरान में उठी कुछ अहम चीज़ों पर ही सारा जोर दूं।

चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन लाई ने मेरे पास सब से हाल में जो पत्र भेजा है, उसमें कई बातें उठाई गई हैं, कई सवाल उठाये गये हैं। जाहिर है कि उन सभी पर पूरी तौर से सोचने विचारने के बाद ही उनका जवाब दिया जायेगा, जल्दबाज़ी नहीं की जायेगी। अभी उन बातों पर गौर किया जा रहा है। मैं इस बहस में उस पत्र को शामिल नहीं करना चाहता। एक तो इसलिये कि हमें श्री चाऊ एन लाई से जो जो बातें कहनी हैं, उनके बारे में सभा को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वह तो सहमत हैं ही। दूसरे यह भी है कि उनको यहां लेने से मैं उनके ब्यौरे में ही उलझकर रम जाऊंगा।

मैं सब से पहले तो श्री कर्गी सिंह जी द्वारा कही गई बात का ज़िक्र करना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया है जिस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उनकी राय में उन्हीं लोगों के साथ पंचशील का समझौता होना चाहिये जो उनके साथ सहमत हों। मुझे तो यह एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मैं तभी तक सहनशील बनने में यकीन करता हूं, जब तक कि आप हमारे साथ सहमत हों। अगर आप सहमत नहीं होंगे, तो मैं आप का सिर तोड़ दूंगा। सहनशीलता और सहनशील बनने का उनका यही नज़रिया है। उनकी पंचशील की यही समझ है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है: "हमें अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहिये।" कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा "हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिये।" ऐसी बातें कहने वाले लोग जोश-खरोश भरी चाहे जितनी भी बातें कहें, लेकिन असल में अन्दर से बड़े कमज़ोर, कम हौसले वाले और जरा-जरा सी बात पर खतरे से डर जाने वाले लोग ही मालूम पड़ते हैं। एक राष्ट्र, एक देश इस ढंग से अपने सामने आने वाले खतरे का, चुनौती का सामना नहीं किया करता। वह चारों तरफ़ यह नहीं देखता कि कोई दूसरा उसकी मदद कैसे कर सकता है। अगर आप खुद ही उस खतरे और उस चुनौती का सामना करने लायक नहीं है, तो फिर दूसरा आपकी क्या मदद कर सकता है? हमें यह बात बिल्कुल साफ़-साफ़ समझ लेनी चाहिये कि मैं भारत के प्रधान मंत्री की हैसियत से, और मेरी सरकार दोनों ही इस बात पर दृढ़ हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल न होने की अपनी नीति नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी नीति पर जमे रहेंगे। लोग जो भी चाहें कहें, पर हम अपनी नीति पर अटल रहेंगे। यह पंचशील का सिद्धान्त, यह उसूल एक ऐसी सचाई है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सचाई तो अपनी जगह है, हमारे उससे सहमत होने, उसकी बिना पर अपनी नीति बनाने, या चीन के उससे सहमत न होने से, वह सचाई तो नहीं मिटती। उसे कोई भी ग़लत साबित नहीं कर सकता। अगर कोई झूठ बोले, तो आप उसका सिर तोड़ देने की बात कहें, वह तो एक दूसरी ही बात है। लेकिन क्या आप यह भी कहना चाहेंगे कि "दूसरा आदमी झूठ बोलता है, इसलिये आप भी सच न बोलिये।" क्या आप इसे मानते हैं?

आज दोपहर को यहां जो बातें कही गई थीं, उनमें से कुछ तो बड़ी अजीबोगरीब थीं। मैं जानता हूं कि यह गुस्सा दिलाने वाली बात है, जरूर है। मैं इस जोश और इस भावना को भी बिल्कुल ठीक समझता हूं कि भारत की इज्जत, भारत के आत्म-सम्मान और भारत की एकता पर किसी को एक उंगली तक नहीं उठाने देनी चाहिये। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डा० राम सुभग सिंह ने इसी सिलसिले में पहाड़ी इलाक़ों और वहां के बाशिन्दों पर बम बरसाने की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जो बात कही है, वह सचमुच बड़ी अजीबोग़रीब है। उससे पता चलता है कि उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रह गया है। वह न बमबारी को समझते हैं, न पहाड़ों को, न इन्सानों को और न दूसरी किसी भी चीज को। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है वह अपना सन्तुलन खो बैठे हैं, गुस्से और जोश से अपने पर काबू खो बैठे हैं। और अगर यह देश संकट के दिनों में इसी तरह गुस्से से काम करने लगे, तो फिर वह संकट का मुकाबला कैसे करेगा। क्या यह संसद् इसी ढंग से काम करेगी? अगर ऐसे कुछ सुझाव मान लिये जायें, तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। अगर सभी लोग एक दूसरे का सिर तोड़ने पर आमदा हो जायें, तो फिर देश की क्या हालत हो जायेगी? और क्या कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हमारे देश की एक इंच ज़मीन भी नहीं जाने दी जायेगी। ऐसी जोशीली बातों में कोई भी सार नहीं। यह तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई लड़कर या किसी दबाव से चाहे तो हमारे देश की एक आधे इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में हम कोई भी दबाव मानने के लिये तैयार नहीं। उस हालत में वह एक इंच या गज़ या एक मील का सवाल नहीं रह जाता। वह तो तब दबाव के सामने सिर झुकाने का सवाल बन जाता है। और हम दबाव के सामने कभी सिर नहीं झुकायेंगे, चाहे हमारे देश का कुछ भी हो।

लेकिन इस तरह की जोश भरी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुझे यहां पार्लियामेंट में बैठे ऐसी आग-बबूलों भरी तक़रीरें नापसंद हैं। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नापसन्द हैं कि अगर आप किसी के किसी काम या उसकी किसी बात को पसन्द नहीं करते तो उस पर बमबारी करते फिरें। लोगों की ऐसी बहुत सी चीज़ें होतीं हैं, जो हमें पसन्द नहीं होती। आचार्य कृपालानी ने मुझ पर कई इल्ज़ाम लगाये हैं। शायद वह सही भी हों। लेकिन उनकी यह बात तो ग़लत है कि मैं ज़रूरत से ज्यादा नर्मी बरतता हूं। दूसरे लोग तो अकसर मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कहते। उन्होंने गांधी की का भी हवाला दिया था। गांधी जी ने और जो भी कहा या किया हो, लेकिन वह कभी भी हमारे इन कुछ लोगों की तरह चीखें-चिल्लाये नहीं थे। यह जरूर है कि वह जो भी कुछ करते थे उस पर अटल रहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा ही बड़ी नरमी से भरी रहती थी। वह अपने विरोधियों और यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी बड़ी नरमी के साथ पेश आते थे, हमेशा उन्हें अपनी तरफ़ लाने की कोशिश में लगे रहते थे। हम गांधी होने का दावा नहीं करते, हम तो उनके दूर के अनुयायी कहलाने लायक़ भी नहीं। लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि ग़ैर-देशों से ताल्लुक़ रखने वाले मामलों में हमें नरमी से, लेकिन मजबूती से, अपनी बात पर अटल रहना चाहिये। हम जिसके आदी बन चुके हैं, उस तरह चीख-चिल्लाकर हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिये। अपनी आंखें बन्द करके, बिना सोचे-समझे एक दूसरे को कोसने वाली बातें नहीं कही जानी चाहिये। "कोल्डवार" (शीतयुद्ध) में इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये। डा० राम सुभग सिंह की तरह बमबारी की बातें नहीं करने लगना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने यह भी कहा था कि हमें चीखना चाहिये; हमें और बुलन्द आवाज़ में बोलना चाहिये। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे सामने एक बहुत गम्भीर मसला है, और ऐसे गम्भीर मसलों के बारे में सिर्फ उत्तेजित हो जाने से या आवेश में आ जाने से कोई बात नहीं बनती। जाहिर है कि ऐसे मामलों में हमें अपनी जगह पर मजबूती से पैर जमाये रहना चाहिये। जहां मजबूती दिखाने की बात हो, वहां मजबूती ही दिखानी चाहिये। लेकिन हवा में तो मज़बूती नहीं दिखाई जाती, हर अच्छी या बुरी चीज़ के बारे में तो मज़बूती नहीं दिखाई जाती। कुछ

चीजें अहम होती हैं, और कुछ इतनी अहमियत नहीं रखतीं। अहमियत रखने वाली चीजों के बारे में तो हमें अपनी जगह पर अटल रहना चाहिये, चाहे कुछ भी क्यों न हो। अगर कोई आदमी हर एक चीज पर अड़ने की कोशिश करे, तो उस का मतलब है कि वह किसी भी बात पर मजबूती नहीं दिखाता। दुनिया में कोई भी आदमी हर एक चीज के बारे में अटल नहीं रह सकता। इस की भी हर आदमी की अपनी-अपनी सीमायें होती हैं, हदें होती हैं। अमरीका और सोवियत संघ बहुत ही ज्यादा, सब से ज्यादा ताकतवर देश हैं, लेकिन वे दोनों भी अपनी अपनी सीमायें जानते हैं कि किस बात पर, किस हद तक वे मजबूती से जमे रह सकते हैं, अड़ सकते हैं। और वे उन हदों से आगे नहीं बढ़ते। अगर उस से आगे बढ़ जाते तो अभी तक कभी की जंग छिड़ गई होती। और दुनिया तहस नहस हो गई होती। हम यहां इस तरह की बातें कहते हैं कि हमें मजबूती से डटना चाहिये, हमें लड़ना चाहिये अपने खून की आखिरी बून्द तक बहा देनी चाहिये--इस तरह की बातें हमारा ध्यान अहम सवालों की तरफ से, वाकई मुश्किल सवालों की तरफ से हटा देती हैं। स्थिति काफी गम्भीर है।

प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई के आखिरी पत्र में कहीं-कहीं बड़ी नरमी से भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कहीं हालत को ज्यों की त्यों, पहले की तरह ही बनाये रखने की, आपस में बैठ कर बातचीत करने वगैरह की बातें कही गई हैं। लेकिन उस में बुनियादी तौर पर कुछ बड़े गम्भीर मसले उठाये गये हैं, ऐसे मसले जो सरकारी तौर पर पहली बार उठाये गये हैं।

अभी मैं यहां बैठा बैठा पीकिंग में हुई किसी एक कांग्रेस में हुई बहसों की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस कांग्रेस में प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने करीब करीब वही सब कुछ कहा है जो इस पत्र में कहा गया है। और जाहिर है कि यह जानने के लिये भी कोई बड़ी अक्लमन्दी की जरूरत नहीं कि कांग्रेस में बोलने वाले दूसरे सभी लोगों ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई का समर्थन ही किया है। इसी बात का समर्थन किया है कि :

> "हमें यह देख कर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि श्री नेहरू ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत कर रहे हैं। किसी ने श्री नेहरू से पूछा : ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करते वक्त वह किस की तरफ़ से बोल रहे हैं ? अब प्रधान मंत्री नेहरू और भारत सरकार पिछली सदी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा चीन के खिलाफ रची गई हमलावर योजना को एक ऐसी सच्चाई मानने लगे हैं, जिस के बारे में अब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता। क्या यह सब श्री नेहरू द्वारा रखे गये पांच सिद्धान्तों से मेल खाता है ....."

इसी तरह की और बहुत बातें भी कही गई हैं। जैसेकि हमारे यहां के कुछ लोगों ने मैकमहोन लाइन के बारे में बड़े जोरदार ढंग से कहा है कि उस से एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिये उसी तरह, उसी लहजे में उधर चीन में भी, मैकमहोन लाइन के खिलाफ इतनी ही जोरदार बातें कही जा रही हैं। तो यह हालत है।

जाहिर है कि इस तरह का सवाल दिल्ली या पीकिंग में प्रस्ताव पास करके या एक दूसरे के खिलाफ़ गर्मागर्मी दिखा कर हल नहीं किया जा सकता। इसे हल करने का तो कोई दूसरा ही तरीक़ा निकालना पड़ेगा--या शांतिपूर्ण ढंग से या लड़ाई के ढंग से ही इसका हल होगा। ऐसे मामलों में ही नहीं, बल्कि सभी मामलों में, दुनिया में हर जगह के समझदार लोग लड़ाई से बचना चाहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भी आज लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी हालत में हम लड़ाई की बातें करें, तो वह एक बड़ा मखौल सा लगता है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कमजोर से कमजोर आदमी या छोटे से छोटे देश के लिये यह कहना एक बिल्कुल दूसरी बात है कि वह किसी भी बुराई के आगे सिर नहीं झुकायेगा, चाहे जो भी हो जाये । यह तो एक दूसरी ही बात है कि हम बुराई के सामने, बेइज्ज़ती और ज़बरदस्ती के सामने सिर नहीं झुकायेंगे और गांधी जी के मुताबिक़ तो एक अकेला आदमी भी यह कह सकता है । लेकिन अगर कोई मुल्क अपनी ताक़त के घमण्ड में वह कहे कि वह अपनी फौजों और बमों के बल पर ऐसा या वैसा कर सकता है, तो वह इस से एक बिल्कुल ही उल्टी बात है । इन दोनों नज़रियों में ज़मीन आसमान का फर्क है ।

आज चीन में क्या हो रहा है ? मैं तीखे अल्फाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आज चीन अपनी ताक़त के घमण्ड में चूर है, जो उस के हमारे प्रति अल्फाज़, उस के बर्ताव, तौर तरीके और ढंग से बिलकुल साफ झलक रहा है ।

और तब यह सवाल सिर्फ मेकमहोन लाइन से एक दो मील इधर या उधर होने का एक छोटा मोटा सवाल नहीं रह जाता । मैं आप भी कहता हूं कि मैकमहोन लाईन इधर उधर एक दो मील का सवाल एक छोटा मोटा सवाल ही है । लेकिन चीन के नक्शों में भारत के बड़े बड़े इलाकों को चीन के इलाकों की तरह दिखाना एक छोटा सवाल नहीं रह जाता । यह एक काफी बड़ा सवाल बन जाता है । हां अगर, किसी टुकड़े को उस में ग़लत ढंग से रखा गया होगा, तो मैं उसे देने के लिये तैयार हो जाऊंगा, मैं वह टुकड़ा दे दूंगा, क्योंकि मैकमहोन लाइन तो एक काफी मोटी सी लाइन है, जो भूटान और बरमा की सीमा के बीच से बरमा तक जाती है। कुछ जगहों पर तो वह बिलकुल साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर इतनी साफ नहीं है और कुछ इलाक़ों में तो उस के निशान भी मौजूद नहीं । ऐसी जगहों और इलाक़ों में आप को और दूसरी बातें देख कर तय करना होता है । जिस आदमी ने वह लाइन बनाई थी, उस का नज़रिया एक मोटे तौर पर यह था कि नदियों, झीलों, वगैरह को ही सीमा माना जाये । इसलिये जब मैं मैकमहोन लाइन की बात कहता हूं तो मेरा मतलब यही होता है कि मोटे तौर पर इसी नज़रियों को माना जाये । लेकिन अगर फिर भी, कुछ ऐसे तथ्य हों या कोई सबूत ऐसे सामने आयें जो इस के खिलाफ हों, तो उस लाइन में थोड़ा हेरफेर किया जा सकता है । वह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं । लेकिन उस का फैसला कुछ तथ्यों और सबूतों की बिना पर ही किया जायगा, किसी के दबाव या ज़बर्दस्ती से नहीं ।

मैं ने बातचीत द्वारा या किसी को मध्यस्थ बनाने या पंच बना कर इस मामले का फैसला करने की भी बात कही थी । उस से मेरा यही मतलब था कि इन छोटे-मोटे मसलों को, छोटी मोटी फेर बदल करने के इन सवालों को किसी पंच या मध्यस्थ के जरिये तय कराया जा सकता है । मैं उन जगहों के नाम भूल रहा हूं । मैं ने शायद लोंगजू और होती, और कुछ ऐसी ही दूसरी जगहों के सिलसिले में ही वह कहा था । होती तो खैर मैकमहोन लाइन पर नहीं है, वह तो उत्तरप्रदेश में है । इन में थोड़ा हेर फेर करने की बातचीत शान्तिपूर्ण ढंग से, दोस्ताना तौर पर चलाई जा सकती है और अगर काफी सबूत मौजूद हों तो उन में कुछ तब्दीली भी की जा सकती है ।

लेकिन आज हम इस पर गौर नहीं कर रहे हैं । आज हम उस से बड़ी चीज़ पर, कहीं ज्यादा अहम मसले पर गौर कर रहे हैं । और वह है चीन का दावा जो चीन के नक्शों में किया जाता रहा है और जिसे प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अब पहली बार अपनी आखिरी पत्र और अपनी स्पीचों में दोहराया है । अब वह दावा और साफ शक्ल में हमारे आगे आ रहा है । इस से पहले तो जब भी कभी उन नक्शों का जिक्र किया जाता था, तो उस तरफ से कह दिया जाता था : "वे बड़े पुराने नक्शे हैं, हम उन्हें नये सिरे से तैयार करेंगे ।" वह जवाब काफी नहीं था, लेकिन एक तरह का जवाब तो

था, आगे कभी जवाब देने की बात तो थी। लेकिन अब तो उस की एक खास शक्ल साफ-साफ उभरती आ रही है। उन नक्शों को ही काफी सही बताया जा रहा है। हमें अभी ठीक-ठीक नहीं मालूम कि चीन किस सीमा को सही मानता है, किन किन इलाक़ों को चीन का हिस्सा समझता है, या उस का दावा करता है। यह एक ऐसा बर्ताव है जो अनुचित है, गैर वाजिब है, ऐसा है जो किसी मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क के साथ नहीं करना चाहिये और खास तौर से तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिये जबकि वे एक दूसरे के दोस्त रहे हों। आज यही सब से बड़ा सवाल हमारे सामने है।

मैं फिर दोहराता हूं कि अभी इस वक्त हम इन छोटी-मोटी जगहों के बारे में परेशान नहीं हैं। हां एक छोटी जगह भी तब बड़ी अहम बन जाती है जबकि कोई जोरजबरदस्ती से, या हमला कर के उसे हम से छीनना चाहे। उस हालत में तो एक गज़ जमीन का टुकड़ा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तब उस हालत में एक गज़ का वह टुकड़ा नहीं बल्कि जोरजबरदस्ती ही खास चीज़ बन जाती है। लेकिन उन छोटी-मोटी जगहों के बारे में आपसी तौर पर बैठ कर बातचीत की जा सकती है। क्योंकि उस पहाड़ी इलाके की कुछ गज़ ज़मीन इधर रहे या उधर, इस से दोनों मुल्कों के लिये कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई हमला कर के, बेइज्ज़ती कर के, जोरजबरदस्ती से उसे लेना चाहे, तो उस में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है।

मुझ पर एक इल्ज़ाम यह भी लगाया गया है कि मैं ने इन अहम मामलों के बारे में पार्लियामेंट को सभी बातें नहीं बताईं, पूरी जानकारी नहीं जुटाई थी। इस में थोड़ी सचाई भी है। मैं आप को बताता हूं कि मैं ने कौन सी जानकारी नहीं जुटाई थी। सिर्फ एक ही ऐसी बात है, जो मैं ने वहां नहीं रखी थी, या जिस की जानकारी नहीं जुटाई थी। और वह है पिछले नवम्बर-दिसम्बर में अकासी चिन के इलाके और वहां बनने वाली सड़क के बारे में। बड़ा होती वगैरह के बारे में हमारे पत्रों, आदि के अलावा, इस मामले की हमें तभी जानकारी मिल गई थी। हम यहां हर छोटी मोटी चीज़ तो नहीं रख सकते, लेकिन मैं मानताहूं कि वह एक काफ़ी अहम चीज़ थी। अकासी चिन के इलाके से जाने वाली सड़क का मामला काफी अहमियत रखता है। हम ने उस वक्त भी यह महसूस कर लिया था। लेकिन हम ने तब उसे यहां नहीं रखा। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या हमारी वायुसेना तमाम इलाकों के फोटो नहीं खींचती लोग शायद यह नहीं समझते कि वह इलाका है किस क़िस्म का। उस की फोटो खींचने की कोशिश करने वाले हवाई जहाज की जान पर बन आती दूसरी तरफ के लोग उसे मार गिराते।

मैं उसके पूरे ब्यौरे में नहीं उलझना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभा यह अच्छी तरह समझ ले कि वे इलाक़े हैं क्या। अकासी चिन का यह इलाका हमारे नक्शों में मौजूद तो है, लेकिन मैं उसे दूसरे सभी इलाक़ों से अलग समझता हूं। इसलिये कि उसके बारे में अभी यह तय नहीं है कि उसका कौनसा हिस्सा हमारा है और कौनसा किसी दूसरे का। यह बात अभी बिल्कुल साफ़-साफ़ तय नहीं हो पायी है। आज से नहीं, कई सदियों से उसके बारे में बहस चली आ रही है। यही बहस चली आ रही है कि उस इलाक़े पर किस देश का अधिकार है। जाहिर है कि मैं ऐसे इलाक़े में कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता। उस इलाक़े का मैकमहोन लाइन से कोई ताल्लुक ही नहीं। वह तो एक बिल्कुल ही अलग इलाक़ा है। हवाई जहाज से उस इलाक़े की फोटो लेना या उस पर बम बरसाना भी व्यवहार्य नहीं है। यह तो नहीं है कि कोई वहां जा ही नहीं सकता, लोग वहां पहुंच सकते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि वह भारत का इलाक़ा नहीं तो फिर वहां बमबारी करने का सवाल ही नहीं उठता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यही तो चीज है कि आप तथ्यों का पता लगाये बिना ही कहने लगते हैं । बात यह है कि अभी तक उस इलाक़े की कोई सीमा तय नहीं हुई है । मैं नहीं कह सकता कि कौनसा हिस्सा भारत का है और कौनसा नहीं । अभी उसका फ़ैसला होना बाक़ी है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : श्री चाऊ एन लाई ने अपने पत्र में हमारे प्रधान मंत्री के एक पिछले वक्तव्य का यह सिद्ध करने के लिये प्रयोग किया है कि यह क्षेत्र चीन का है । उसी तरह के वक्तव्य का उन्होंने अपने इस पत्र में प्रयोग किया है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हो सकता है । माननीय सदस्य ऐसा सोच सकते हैं । अब या तो मैं उनके सामने सभी तथ्य रख दूं, या उन्हें भ्रम में रखूं या उन्हें बेबुनियाद तक़रीरें करने दूं । मैं इसके बारे में करूं क्या ? मैंने आज जो कोई वक्तव्य सुने, वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । इसीलिये मुझे कहना पड़ता है कि मैं इन सीमाओं में भेद करता हूं, इन्हें जानता हूं । छोटे-मोटे हेर-फेर को छोड़कर, एक मोटे तौर पर मैकमहोन लाइन ही हमारी तयशुदा सीमा है, हद है । सुबनासिरी इलाक़े, और कुछ दूसरे इलाक़ों में भी, भारत सरकार ने मैकमहोन लाइन को ठीक नहीं समझा था, और हमने इसीलिये उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी थी । हमें कई चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा । लेकिन एक मोटे तौर पर हमारी सीमा नदियों या झीलों वग़ैरह की बिना पर ही बनाई गई है । हम इसी को सही कसौटी मानते भी हैं । हम यहां वहां कुछ खास वजहों से कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां करने की बात तो मानते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर मैकमहोन लाइन ही हमारी सीमा है । यदि आपसी बातचीत और समझौते के जरिये इस लाइन के एक मील इधर या उधर के क्षेत्र में कुछ तब्दीली करनी हो, तो वह की जा सकती है । और उसी के लिये, ऐसे समझोते के लिये ही, मैंने मध्यस्थ या पंच के जरिये फैसला कराने की बात कही थी । लेकिन चीन जिन बड़े-बड़े इलाकों और ज़मीन की पट्टियों को चीन में मिलाने की मांग कर रहा है, वह तो बिल्कुल ही बे सिर पैर की मांग है और जाहिर है कि उसके बारे में किसी मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं । चीन अपनी मांग का आधार आज से सदियों पहले के कुछ वाक़यात को बना रहा है । कल मैंने इस सिलसिले में राज्य-सभा में कहा था कि अगर इसी दलील को लागू किया जाये, सदियों पुराने दावों को देखा जाये तो इतने बड़े चीन राज्य का शायद बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से निकल जायेगा । चीन इतना बड़ा राज्य बना कैसे ? क्या पंचशील के सिद्धान्त पर चलकर ? चीन में राज्य को दूसरों पर हमले करके ही इतना बड़ा बनाया गया है । बात चाहे अभी कुछ साल पहले की हो, या सौ या दो सौ-पांच सौ साल पहले की हो, उससे इस सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता कि दूसरे मुल्कों पर हमले करके और उन्हें जीतकर ही चीन इतना बड़ा राज्य बना है । सभी बड़े बड़े देश ऐसी ही हिंसाभरी जीतों से बड़े बने हैं । और अगर आप अब चीन के इस नये सिद्धान्त को, इस नयी दलील को लागू करें, तो सभ्यता शुरू होने के समय चीन एक इतना ही बड़ा राज्य तो पैदा नहीं हुआ था, जितना कि वह आज बन गया है । अगर चीन अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दुहाई देता है तो उसे पहले ज़माने के चीनी साम्राज्यवाद के कामों को भी तो देखना चाहिये । उसी दलील के मुताबिक, हम भी तो कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य, कुशान साम्राज्य और चन्द्रगुप्त का साम्राज्य आधे मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था ; और इसलिये हमें वह सब मिलना चाहिये । यह एक अजीब सी दलील है । यह दलील हमें पहले के ज़माने

†मूल अंग्रेजी में

की तरफ़ ले जाती है, और आज की सारी चीज़ें उसमें उलट-पुलट जाती हैं। असल में, ताकतवर और हमले का इरादा रखने वाले मुल्क ही ऐसी दलीलें देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमियों की तरह, कभी-कभी मुल्कों को भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसलिये इस मामले में अब हमें बुनियादी तथ्यों को देखना चाहिये।

ये बुनियादी तथ्य है : पहला तो यह कि चीन के नक्शों वग़ैरा में जो दावा गोलमोल तरीके से किया जाता रहा है अब उसे बिल्कुल साफ-साफ ढंग से दोहराया जा रहा है। इस दावे को भारत और कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। इसमें शको-शुबह की जरा भी गुंजाइश नहीं। इस बे सिर पैर के दावे के बारे में किसी को भी मध्यस्थ या पंच बनाने का सवाल ही नहीं उठता। शायद श्री खाडिलकर ने हां इसके बारे में कहा था कि इस अजीब से दावे को मानने का मतलब है समूची भौगोलिक स्थिति को हां बदल देना, यानी पूरा हिमालय प्रदेश चीन को उपहार में दे देना। भारत का वजूद रहे या न भी रहे लेकिन इस दावे को तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। यह मामला यहां खत्म हो जाता है।

और, जहां तक कुछ खास-खास जगहों की हद तय करने का सवाल है, उसके बारे में जरूर बात चीत की जा सकती है, हां लेकिन एक शर्त पर कि बात चीत शान्तिपूर्ण ढंग से की जाये, आपसदारी से की जाये। लोंगजू के बारे में, आपने हमरा पत्र भी देखा होगा कि हमने उसे अपने इलाक़े म माना है। हमारा यही ख्याल है। चीन का ख्याल है कि वह हमारे इलाक़े में, हमारी सरहद में नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात ठीक समझते हैं। लेकिन उसके बारे में हमने चीन से कहा है कि हम लोंगजू में अपनी सेनायें न भेजने के लिये इस शर्त पर तैयार हैं कि चीन भी वहां से अपनी सेनायें हटा ले। और, फिर नक्शों और चार्टों वग़ैरह को सामने रखकर इन दोनों दावों पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि शान्तिपूर्ण ढंग से उसमें छोटी-मोटी तब्दीली की भी जा सकती है। हम शान्तिपूर्ण ढंग से सभी छोटी-मोटी तब्दीलियों के बारे में बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

हमारे सामने मैकमहोन लाइन है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा उससे मिलती है। तिब्बत के बारे में १९५४ में हमने एक संधि की थी। जिसमें तीर्थ-यात्रियों व्यापारियों और अन्य लोगों के लिये कई पहाड़ी दर्रों का जिक्र किया गया था। एक तरह से तो उन दर्रों से ही सीमा बन जाती है। और अब इस पत्रमें शिपकी ला दर्रे को चीन का हिस्सा बता कर १९५४ की उस संधि को तोड़ा गया है।

डा० राम सुभग सिंह ने कुछ इस तरह की बात कही थी कि कोई भी नहीं जानता कि चीन ने भारत के किन-किन इलाक़ों पर कब्ज़ा कर रखा है। मैं तो समझता हूं कि यह बात हर एक भारतीय जानता है या उसे जाननी चाहिये। यदि किसी को न भी मालूम हो, तो ऐसे वक्तव्य देने से पहले उसे इन सब का पता लगा लेना चाहिये।

लद्दाख़ के जिस इलाके का मैंने जिक्र किया था, सड़क के उस इलाक़े को छोड़कर, बाकी सभी इलाक़ों के बारे में हमें मालूम है कि चीनी कहां हैं। अभी इस वक्त लोंगजू के तीन या चार मील के इलाक़े के अलावा, मैकमहोन लाइन के इस तरफ कहीं भी चीनी फौज़ें नहीं हैं। लोंगजू के इलाक़े में उनका एक छोटा सा दस्ता है। लोगों को शायद कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी सीमाओं पर हमार चीनी फौज़ें मौजूद हैं, और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यह ग़लत है। और ऐसा करना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका इधर से माकूल जवाब भी दिया जायेगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि अभी इस वक्त चीनी फौजों के जमाव का खतरा इतना खास नहीं है जितना कि पीकिंग में इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ लफ्ज़ों का है। पीकिंग में कुछ ऐसी अजीबो-गरीब बातें कही जा रहीं हैं जिन्हें मानना या जिनके सामने हमारा झुकना नामुमकिन है। वैसे एक मोटे तौर पर हमारा रख हमेशा दोस्ताना ही रहेगा, आखिरी दम तक दोस्ताना रहेगा, क्योंकि दूसरे किसी भी रुख को हम ग़लत समझते हैं।

हम अपने आप पर काबू न रखकर, गुस्से में आ सकते हैं। लेकिन गुस्से में आना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं, कम से कम एक राष्ट्र को तो गुस्से में नहीं आना चाहिये, खास तौर से तब जब कि उसके सामने गम्भीर समस्यायें खड़ी हों। उसे मज़बूती से काम करने के साथ ही साथ, अपने-आप पर काबू भी रखना चाहिये। यहां मैं यह भी बता दूं कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि पेकिंग में कुछ बेसिर पैर के दावे दोहराये जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि तिब्बत में हमारे मिशनों और व्यापार एजेन्सियों के साथ चीन के अधिकारी लगातार बड़ा बुरा बर्ताव करते आ रहे हैं। हमने उसकी शिकायतें भी की हैं, और चीन की तरफ से उनकी सफ़ाइयां भी पेश की गई हैं। लेकिन लगता यही है कि वे जान बूझकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वे हमारा वहां रहना ही मुश्किल बना देना चाहते हैं।

आचार्य कृपालानी ने मेरे नज़रिये के बारे में बहुत-कुछ कहा है। मैं उनकी तवज्जह श्वेत-पत्र के सफ़ा ७७ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह खुद उसे देख लें। मैं पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। उस सफे पर चीनी वक्तव्य के जवाब में हमारे वैदेशिक कार्य सचिव का एक वक्तव्य दिया गया है। उसे पढ़ने से आचार्य जी को पता चल जायेगा कि हमारा नजरिया नरमी के साथ ही साथ मजबूती से अपनी जगह खड़े रहने का ही रहा है।

श्वेत-पत्र में शामिल किये गये वक्तव्यों में से एक में समाजवादी पार्टी का कुछ जिक्र भी आया है। मैं खुद उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। मैं उस हवाले के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों से क्षमा चाहता हूं। मुझे उस पर खेद है। लेकिन मैं आप को बता दूं कि बम्बई की उस घटना से मुझे बड़ा धक्का लगा था, इसलिए कि हर राज्य के प्रधान को आलोचना और बहस के दायरे से अलग रखा जाता है, और उस पर कोई चोट करने से जनता का गुस्सा उबल पड़ता है। बम्बई में अध्यक्ष माओ की तस्वीर को लेकर जो कुछ भी किया गया था, उससे चीन की जनता के ख्यालात एकाएक हमारे खिलाफ़ उभर पड़े। हमारे दुश्मनों ने उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया। मुझे उस घटना से काफ़ी धक्का लगा था।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : उस घटना के तुरन्त बाद, स्वयं समाजवादी पार्टी ने वहीं उसकी निन्दा की थी। क्या इस बात की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान नहीं दिलाया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है। लेकिन मैंने खेद भी प्रकट कर दिया है कि वहां उसका उल्लेख इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिये था।

मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले पर, इस नजरिये से विचार करे। इस में माननीय सदस्यों को शीतयुद्ध या कम्युनिज्म के बारे में अपने नज़रिये को बीच में नहीं लाना चाहिये। वैसे इस में कम्युनिज्म की बात तो एक तरह से आ ही जाती है, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट राज्य है। उस तरह से इस में कम्युनिज्म का सवाल तो उठता ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप शीत युद्ध

†मूल अंग्रेज़ी में

या कम्युनिज्म के बारे में अपने पहले से बने-बनाये नज़रियों को बीच में ले आयेंगे, और उन नज़रियों से इस मामले पर गौर करेंगे तो इस परिस्थिति को समझने में आपको मुश्किल पड़ेगी। आज इस परिस्थिति की असलियत वह है कि हमें एक महान और एक बड़े ताकतवर मुल्क का सामना करना है जो हमलावर बन रहा है। हमें इस असलियत का सामना करना है; इसका कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि हमलावर होने के साथ वह कम्युनिस्ट है या गैर-कम्युनिस्ट।

इसलिए इन कई मसलों को एक दूसरे से उलझाइये मत। शीत-युद्ध की बात तो यह है कि दुनिया के सभी समझदार आदमी आज उसका खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं; और अगर हम भी, जो अभी तक शीत-युद्ध के खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, आज उसमें शामिल हो जायें, तो वह एक बड़े दुःख की बात होगी। इसलिये कि शीत-युद्ध शुरू करने वाले मुल्क तो उससे दूर जा रहे हैं, और हम जो उसकी मुखालफ़त करते थे, उसमें शामिल हो जायें। यह बड़े दुःख की बात होगी। इसलिए हमें शीत-युद्ध से दूर ही रहना चाहिये। शीत-युद्ध में शामिल होना दिमाग़ी तौर पर अपनी हार मानना है। शीत-युद्ध का तरीका किसी भी सवाल को हल करने का समझदारी का तरीक़ा नहीं है।

शायद डा० राम सुभग सिंह ने ही भूटान और सिक्किम का जिक्र किया। मुझे उससे खुशी हुई है, क्योंकि मैं भी उसका जिक्र करना चाहता था, और इस तरह मुझे उसकी याद आ गई है। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपने आखिरी पत्र में कहा है :

> "आप ने अपने पत्र में चीन और सिक्किम के बीच की सीमा का भी उल्लेख किया है। चीन और भूटान के बीच की सीमा के प्रश्न की तरह ही, यह प्रश्न भी हमारी वर्तमान चर्चा के क्षेत्र में नहीं आता।

मैं प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई की इस बात को नहीं मानता। वह प्रश्न हमारी चर्चा के दायरे में बिलकुल है। अगर उनका ख्याल हो कि वह उस सवाल को भारत के सवाल से अलग रख कर तय कर लेंगे, तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। हमने खुले तौर पर सिक्किम और भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और हम ने बिलकुल ठीक किया है। अगर उन पर हमला होगा, तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए सिक्किम और भूटान की स्थिति समझना भी हमारे लिये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी सीमा पर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसे भारत की सीमा में हस्तक्षेप करना ही माना जायेगा।

शायद श्रीमती रेणुका राय ने पूछा था कि क्या अभी तक भूटान की सीमा का उलंघन हुआ है। मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ।

डा० राम सुभग सिंह ने मुझ से एक और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा था। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपने पत्र में एक तार का हवाला दिया है, जो हमें ल्हासा से १९४७ में मिला था। बात सही है। श्री चाऊ एन लाई ने उस तार का हवाला देकर यह बताने की कोशिश की है कि हमारे आज़ाद होने के हाल ही बाद भी तिब्बत ने हम से कुछ क्षेत्र मांगा था। यह सही है कि ल्हासा के तिब्बत ब्यूरो की तरफ से हमारे नाम एक तार भेजा गया था, जो ल्हासा में स्थित हमारे मिशन ने हमारे पास भेजा था। उस में दावा किया गया था कि भारत और तिब्बत की सीमा का कुछ तिब्बती इलाका तिब्बत को लौटा दिया जाय। हम ने उसका जवाब भेज दिया था। उस पत्र में यह नहीं बताया गया कि हम ने १९४७ में उसका ठीक-ठीक क्या जवाब भेजा था। हम ने अपने जवाब में तिब्बत सरकार से यह आश्वासन मांगा था कि जब तक दोनों मुल्कों में उन बातों पर, जो दोनों में से कोई देश उठाना चाहे, समझौता न हो जाये तब तक वह मौजूदा आधार पर सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पता नहीं उस तार का मतलब क्या है। लेकिन सीमा से ताल्लुक रखने वाले इन छोटे-छोटे मामलों पर, मिग्यितिन वगैरह के मामलों पर, बहस करते वक्त, सभा को यह नहीं भूलना चाहिए कि इनके बारे में तिब्बत की पुरानी सरकार के साथ बहुत अर्से से कुछ विवाद चल रहा है, अंग्रेजी शासन के दिनों में भी इन मसलों पर विवाद चल रहा था। कुछ ऐसे छोटे-मोटे इलाके हैं जिनके बारे में भारत सरकार और तिब्बत सरकार के बीच बहस चलती रही है। कुछ नये झगड़े भी उठे वे। हो सकता है कि उस तार में उन छोटे-मोटे इलाकों का ही जिक्र किया गया हो।

चीन सरकार ने जो अब एक नया नज़रिया अपनाया है, उसकी एक मिसाल देखिये। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास चीन सरकार की तरफ़ से एक शिकायत आई थी कि हम ने चीन की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया था। मुझे उस पर ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसमें कहा गया था कि हमारे एक छोटे से जहाज़—शायद एक छोटे से युद्ध-पोत ने उनकी समुद्री-सीमा का उल्लंघन किया था। वह युद्ध-पोत 'मगर' नामक बड़े जहाज़ के लिऐ सामान ले जा रहा था। उसी दौरान में, वह हांगकांग के पास से गुज़रा था, और इस में शक नहीं कि वह चीन की समुद्री सीमा में शायद १२ मील तक अन्दर गया था। शिकायत में कहा गया है कि उस युद्ध-पोत से रुकने के लिए कहा गया था, पर उसने उसे अनसुना कर दिया था। अभी तक 'मगर' जहाज़ लौटकर नहीं आया है। लेकिन हमें सूचना मिली है कि उससे रुकने के लिए नहीं कहा गया था, और इसीलिए वह आगे बढ़ता गया था। यह एक अजीब सी बात है कि एक इतनी छोटी सी बात को तूल दिया जा रहा है।

लेकिन इसी सिलसिले में एक दूसरा वाक़या भी बताया गया है।

> "गत वर्ष आपके क्रूजर जहाज़—"मैसूर"—ने भी यही किया था; वह हमारी समुद्री-सीमा से होकर गया था।

यह क्रूजर जहाज़—मैसूर—चीन और कुछ दूसरे देशों में सद्भावना मिशन पर गया हुआ था। वह हांगकांग, चीनी शंघाई भी गया था और शायद जापान वगैरह भी गया था। मुझे ठीक से पता नहीं। हां, वह शंघाई जरूर गया था। बड़े ताज्जुब की बात है कि अब एक साल बाद उसका इस तरह हवाला देकर शिकायत की जा रही है। अजीब सी बात है।

इस सिलसिले में बहुत से सवाल पैदा होते हैं, और हमें उन सभी पर बड़ी सावधानी, धीरज, मजबूती और बर्दाश्त के साथ गौर करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सभा उतनी मजबूती और उतनी बर्दाश्त से ही काम करेगी।

अगर मैं ने इससे पहले सभा के सामने कुछ कागजात पेश न करने की ग़लती की थी, तो वह ग़लती अब नहीं होगी। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। उस वक्त हम यही चाहते थे कि उन मसलों पर बातचीत चलने के दौरान में उनका प्रचार न हो, क्योंकि उससे हालात बिगड़ने का खतरा था। और, चीन सरकार की तरफ से जवाब आने में भी कई महीने लगते हैं। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपना यह जवाब भी ठीक छै: महीने बाद दिया है, मेरे मार्च के पत्र का जवाब दिया है। जवाब के इन्तजार में वक्त बर्बाद होता रहता है। जो भी हो, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें पार्लामेंट और समूचे देश को इन सभी घटनाओं से अवगत रखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं यह भी नहीं चाहता कि सभा यह सोचने लगे कि हमारे देश की सीमाओं पर कोई बड़ी गम्भीर चीज़ होने वाली है। मुझे उसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं है। वह सब इतना आसान नहीं है। लेकिन बुनियादी मुश्किल तो चीन सरकार के इस बदले हुए नज़रिये से पैदा होती है। चीन सरकार ने तो अब बिल्कुल साफ-साफ अल्फ़ाज़ में एक ऐसी मांग उठानी शुरू कर दी है, जिस पर गौर करना भी

हमारे लिए नामुमकिन है । लेकिन अगर आप उस बड़ी मांग को, चीन सरकार के उस दावे को अलग रख कर देखें, तो आप को पता चलेगा कि चीन सरकार अभी इस वक्त उस पर जोर भी नहीं दे रही है । अभी इस वक्त चीन सरकार हालत ज्यों की त्यों बनाये रखने के लिए तैयार है । लेकिन उसकी मांग तो है । ठीक उसी तरह जैसे कि नक्शे थे, जो हमें बार-बार याद दिलाते रहते थे कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है । और, अब वह चीज़ ज्यादा साफ-साफ शक्ल में हमारे सामने उभर आई है । सिर्फ इसी मायने में, मैं कहता हूं कि हालत बिगड़ गई है । हालत बिगड़ने से मेरा मतलब यह नहीं कि हमारे देश की सीमाओं पर एकाएक कोई बड़ी गम्भीर चीज़ होने वाली है ।

मेरी अर्ज़ है कि आप इस मसले पर कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट-विरोधी नज़रिये से विचार न करें । सभा ने सोवियत सरकार की ओर से जारी किया गया बयान देखा होगा । सभा यह भी जानती है कि सोवियत सरकार और चीन सरकार के बड़े नज़दीकी ताल्लुकात हैं । उस बयान को जारी करना ही बताता है कि सोवियत सरकार इस पूरी परिस्थिति पर, इन हालात पर एक ठंडे दिल से, बिना किसी की तरफ़दारी के, ग़ौर कर रही है । हम उस का स्वागत करते हैं । हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों महान् देशों—भारत और चीन—के बीच उठने वाले बड़े-बड़े मसलों को हल करने के लिये ग़लत तरीके अपनाये जायें । वह बिल्कुल ग़लत होगा । हमें अपनी गरिमा बनाये रखना चाहिये, और साथ ही मजबूती से अपनी जगह पर खड़े भी रहना चाहिये । इस में शक नहीं कि स्थिति कठिनाइयों से भरी हुई है—दूसरी कठिनाइयों के अलावा, कुदरती बनावट वगैरह की कठिनाइयां भी हैं । लेकिन याद रखिये कि ऐसी कठिनाइयां सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, दूसरी ओर से ज़बर्दस्ती घुसने की कोशिश करने वालों के सामने भी हैं । हजारों मील का पहाड़ी इलाक़ा पार करना आसान नहीं । इसलिये दोनों ही तरफ करीब-करीब एक सी कठिनाइयां हैं ।

खैर, हमारी सेनायें इस मामले में पूरी चौकन्नी हैं, उन्हें सारी हालत की पूरी वाक़फियत है । हमारी सेना के लोग बहादुर और तजुर्बेकार हैं ; और जब उन्हें कोई मुश्किल काम करना पड़ता है तो वे बड़े ठंडे दिमाग़ से, लेकिन बड़े कारगर ढंग से, उसे अंजाम देते हैं । मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसा ही करेंगे ।

इस प्रस्ताव पर कई संशोधन आये हैं । जाहिर है हम कोई भी ऐसा संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं, जिस में हमारी नीति की बुराई की गई हो ।

†**आचार्य कृपलानी** : श्री डांगे ने कहा है कि आप की सरकार दलाई लामा की आर्थिक सहायता कर रही है । क्या यह सही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तिब्बत और दलाई लामा का जिक्र नहीं किया है, इसलिये कि उस का इन मामलों से कुछ थोड़ा ताल्लुक तो है, और उस का कुछ असर भी पड़ा है, फिर भी वह एक बिल्कुल ही अलग मसला है । जहां तक दलाई लामा का ताल्लुक है, मैं 'आर्थिक सहायता' का मतलब नहीं समझा । हम ने उन को यहां रखने पर, कुछ रुपया-पैसा खर्च किया है, जरूर किया है ; लेकिन हम ने उन को खास तौर पर अलग से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी । मसूरी में उन के रहने पर कुछ खर्च जरूर हुआ है और हम दूसरे शरणार्थियों पर भी कुछ खर्च कर ही रहे हैं ।

इस सिलसिले में भी, सभा को मालूम ही है कि हम ने दलाई लामा के कुछ बयानात के बारे में अपने ख्यालात जाहिर कर दिये हैं । हम उन की बातों से सहमत नहीं हैं ।

श्री डांगे और आचार्य कृपालानी ने जिस समस्या का जिक्र किया था, वह हमारे लिये काफी मुश्किल रही है । उस पर कुछ बहस भी उठ खड़ी हुई थी कि हमारे यहां शरण लेने वाले व्यक्ति को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरल ल नेहरू]

कितनी आजादी दी जाये, उस का सम्मान हम चाहे जितना करें। जाहिर है कि यह एक संवैधानिक सवाल है। हम और हमारे देश की जनता दलाई लामा की बड़ी इज्ज़त करते हैं। यह सही है। लेकिन साथ ही, हम ने उन से कई बार कह दिया है कि उन्हें भारत को उस के एक दोस्त मुल्क के खिलाफ कार्यवाहियां करने के लिये अड्डा नहीं बनाना चाहिये। यहां मैं यह भी कहूंगा कि कुल मिला कर उन्हों ने काफ़ी अर्से तक इस का ख़्याल भी रखा ; उन की तकलीफ़ और उन पर पड़ने वाले दबावों को देखते हुए, मैं कहता हूं कि उन्हों ने एक अर्से तक अपने ऊपर काफी काबू भी रखा। लेकिन कभी-कभी वह अपने उस दायरे से बाहर भी चले गये, और तब हमें उन के कुछ बयानात का खंडन भी करना पड़ा है। हम उस के बारे में कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन के उन बयानात में वह कुछ ज्यादा आगे बढ़ गये थे। इसीलिये हम ने उन का खंडन किया था।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि एक तरह से उन में हमारी नीति की निन्दा ही है। लेकिन श्री नलदुर्गकर का एक संशोधन है, जिसे अगर सभा चाहे, तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : 'नेफा' क्षेत्र का विस्तार लगभग ३०,००० वर्गमील है। चीन ने उसे अपने नक्शों में अपने क्षेत्र की तरह शामिल किया है। अंग्रेज़ शासक 'नेफा' क्षेत्र को शेष भारत से बिल्कुल अलग रखते थे। इसलिये वहां भारत से अलगाव की कुछ प्रवृत्तियां मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में उन पर चीनी प्रचार का काफी असर पड़ सकता है। भारत सरकार उस चीनी प्रचार का प्रभाव खत्म करने के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अब वहां शिक्षा भी है और प्रचार भी किया जा रहा है। पुराने जमाने में भी 'नेफा' के अधिकांश क्षेत्र में कोई प्रशासन नहीं था। अब वहां धीरे-धीरे प्रशासन आता जा रहा है। अब वहां पढ़ाई-लिखाई, प्रशासन और भी सभी चीजों का फैलाव बढ़ता जा रहा है।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से काम लिया है, उस के लिये वह कृतज्ञता के पात्र हैं। उन्हों ने बहुत ही ठीक कहा है कि इस चीनी रवैये की जड़ में उस का ताकत का घमण्ड है। साम्राज्यवाद अब केवल पाश्चात्य देशों का एकाधिकार नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि तिब्बत की मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। इस चीनी साम्राज्यवाद को आरम्भ में ही खत्म कर दिया जाना चाहिये।

इतिहास हमें यही बताता है कि साम्राज्यवाद को खुश कर के उस की बढ़ती को नहीं रोका जा सकता। प्रधान मंत्री ने इस मामले में जो दृढ़ता दिखाई है, उस का समर्थन हमारा पूरा देश एक स्वर से करेगा।

अन्त में, मैं श्री डांगे को धन्यवाद देता हूं कि उहों ने चीन की ओर से गारन्टी दी है कि वह हमला नहीं करेगा। पर मैं पूछता हूं कि श्री डांगे का चीन के साथ क्या सम्बन्ध है ? वह चीनी हैं, या भारतीय ? मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें कुछ अधिक यथार्थवादी और देशभक्त बनना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि क्या चीन ने भारतीय प्रदेश में कोई हवाई अड्डा बनाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में, चूशू में केवल एक ही हवाई अड्डा है, जो आज से ४–५ साल पहले बनाया गया था। मैं वहां गया था ; लेकिन वहां कोई भी चीनी हवाई अड्डा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में